वर्ष: 7 अंक: 01

1-15 जुलाई, 2026 (निःशुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

हमें फॉलो करें @NISPIBIndia

ई-कॉपी के लिए QR स्कैन करें

न्यायिक सुगमता का युग

नया कानून-नया विश्वास

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दो गौरवपूर्ण वर्ष, नागरिक-केंद्रित न्याय व्यवस्था के निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा के बन गए हैं प्रतीक...

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

6 जुलाई जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि

देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा

अपने प्रखर राष्ट्रवादी विचारों से मां भारती को गौरवान्वित करने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के विकास में उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय योगदान देते रहे। उनके लिए देश की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उत्तर में कश्मीर से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उन्होंने देश की इंच-इंच भूमि और जम्मू-कश्मीर से दो प्रधान, दो विधान, दो निशान समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को सदैव करता रहेगा प्रेरित...

राष्ट्र के अमर सपूत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म-जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की आन-बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके आदर्श एवं सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुमूल्य हैं।

– नरेंद्र मोदी, **प्रधानमंत्री**

न्यू इंडिया
समाचार

वर्ष: 7, अंक: 01 | 1-15 जुलाई, 2026

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

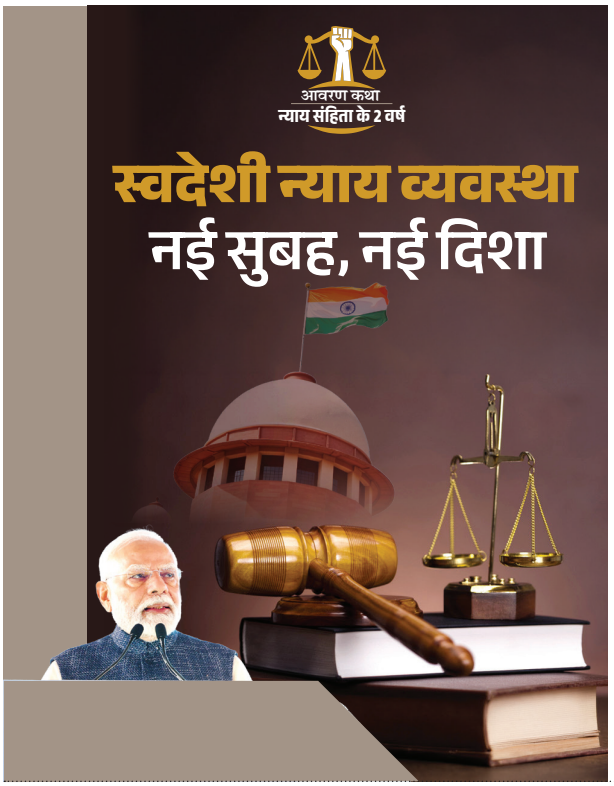

आवरण कथा

दो सदी की दूरी तय करते हुए 21वीं सदी में भारत को गुलामी की छाया से मुक्त अपना कानून मिला। इसी का परिणाम है कि नागरिक हों या पुलिस और अदालतें, बीते 2 वर्षों में न्याय की किताब और भाषा दोनों बदल गई है। इस नए बदलाव से भारत का जन-जन देख रहा है स्वदेशी न्याय व्यवस्था का नया सूर्योदय... | 14-23

भारत के सबसे लंबे समय से सेवारत निर्वाचित प्रधानमंत्री

सेवा, साहस और राष्ट्र निर्माण की अनवरत साधना के प्रतीक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रगति पथ पर अग्रसर... 12 वर्ष की विकास यात्रा एक युग के रूप में हो चुकी है स्थापित | 6-10

ऐतिहासिक नेतृत्व, वैश्विक सराहना

नया भारत, समर्थ भारत

पीएम मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। इस गौरवपूर्ण अवसर पर वैश्विक मंच से मिले बधाई संदेश | 11-12

समाचार सार | 4-5

अहमदाबाद मेट्रो समेत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय | 13

कुशल भारत की ओर मजबूती से बढ़ते कदम
बीते 11 वर्षों में देश के लाखों लोग बनाए गए कुशल और सशक्त | 26-27

तकनीक से परिवर्तन का नया युग
फ्लैगशिप : डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 11 वर्ष | 28-30

नए भारत के कार्यबल का सशक्तीकरण
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना में 56 लाख कर्मचारी हो चुके हैं पंजीकृत | 31

आधुनिक कनेक्टिविटी और विकास का नया अध्याय
सूरत-दमन में 23,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास | 32-34

वीरता को सम्मान...
रक्षा अलंकरण समारोह-1 में राष्ट्रपति द्रोपदी मुमू ने 51 वीरों को किया सम्मानित | 35

दुनिया को प्रेरित करती रहती है भारत की विकास गाथा
शासी परिषद की बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता | 36-37

व्यक्तित्व : गुलजारी लाल नंदा
जिन्होंने मुश्किल समय में संभाली देश की कमान | 38

1 जुलाई, 2026 से विकसित भारत - जी राम जी लागू

ग्रामीण भारत में अब 125 दिन की रोजगार गारंटी

जी राम जी में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम की मांग करेंगे, उन्हें हर वित्तीय वर्ष में दी जाएगी 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी | 24-25

प्रकाशक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **पत्राचार और ईमेल के लिए पता:** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003. **ईमेल- response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812**

संपादक की कलम से...

नया कानून, नई दिशा
न्याय व्यवस्था के सशक्तीकरण का नया युग

सादर नमस्कार।

आज राष्ट्र विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में जुटा हुआ है। इस संकल्प को साकार करने के लिए हम सब ने पंच प्रण लिए थे। उनमें से एक प्रण यह था कि हम अपने आप को गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त करेंगे। देश को भारतीय सोच एवं भारतीय पहचान के साथ एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। इस प्रण की पूर्ति की दिशा में सरकार ने 1 जुलाई, 2024 को औपनिवेशिक युग के तीन कानूनों को रद्द करते हुए न्याय की भारतीय अवधारणा पर आधारित तीन नए कानून लागू किए।

भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बदले में देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए। इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा और मानव अधिकारों को प्राथमिकता दिलाना तथा न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है। ये कानून साइबर अपराध, संगठित अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने और इनसे पीड़ित लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की क्षमता रखते हैं। पिछले दो वर्षों में तीनों कानून न्यायिक सुगमता के नए युग के रूप में स्थापित हो चुके हैं। भारत की पूरी न्याय प्रणाली में अब भारतीय आत्मा है। इन दो वर्षों की यात्रा ही इस बार के हमारे अंक की आवरण कथा बनी है।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में मुश्किल घड़ी में देश की कमान संभालने वाले गुलजारी लाल नंदा, फ्लैगशिप में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, विकसित भारत रोजगार योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर 6 जुलाई को जन्म-जयंती पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बैक कवर पर जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर विशेष सामग्री समाहित है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

मिलती है देश की प्रगति व सरकारी पहलों से जुड़ी जानकारी

मैं 'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका का डिजिटल एडिशन पढ़ता हूं। यह पत्रिका देश की प्रगति व सरकारी पहलों से जुड़ी जानकारीपूर्ण अपडेट्स देती है। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं।

sachingour231@gmail.com

देश की विरासत पर महसूस होता है गर्व

मैंने 'न्यू इंडिया समाचार' के ताजा अंक में जनगणना 2027 पर कवर स्टोरी पढ़ी। इस स्टोरी के लिए आपका धन्यवाद! यह इतनी विस्तृत और व्यवस्थित है कि न केवल प्रक्रिया को ठीक से समझाती है, बल्कि सभी शंकाओं को भी दूर करती है। मीडिया के अन्य माध्यमों से कई तरह के संदेह पैदा हो रहे थे, जो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद अब स्पष्ट हो गए हैं। मुझे कुमुदिनी लाखिया के बारे में पढ़कर भी बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी टीम की सराहना करती हूं कि उन्होंने हमारे देश की ऐसी हस्तियों को खोजा, जिनके बारे में मैं अपने बच्चों को बता सकती हूं और अपने देश की विरासत पर गर्व महसूस कर सकती हूं।

शिप्रा अब्राहम

shipra.abraham@gmail.com

पत्रिका विद्यार्थियों के लिए लाभदायक

मैं इस पत्रिका का नियमित पाठक तो नहीं रहा लेकिन अपने टीचर के आदेशों का पालन करते हुए हाल ही में 'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका के मई के प्रथम संकलन को पढ़ा। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि यह पत्रिका विद्यार्थियों के लिए कितनी लाभदायक है। इस पत्रिका में यूपीएससी के सभी विषयों के बारे में उचित और तथ्यात्मक जानकारियां उपलब्ध हैं। इसका लाभ मुझे हाल ही में दिए गवर्नेंस के टेस्ट में मिला, क्योंकि इस संकलन के अंतर्गत 'स्वयं सहायता समूहों' के बारे में वर्णन था जो यूपीएससी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। इस पत्रिका में करेंट अफेयर्स की उपलब्धता उत्कृष्ट स्तर की है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। मैंने इस पत्रिका को पढ़कर यह निश्चय किया है कि मैं इस पत्रिका का नियमित पाठक बनूं। मैं इसे पढ़ने के बाद अन्य लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप भी इस पत्रिका को रोचकता से पढ़ें और इसका लाभ उठायें।

वैभव सोनी

Vaibhavsoni074@gmail.com

जानकारी देने वाली पत्रिका पढ़ने के लिए रहता हूं उत्सुक

मैं अपने घर पर नियमित रूप से कन्नड़ भाषा में न्यू इंडिया समाचार पत्रिका की कॉपी पढ़ता हूं। यह बहुत जानकारी देने वाली पत्रिका है। मैं इसे पढ़ने के लिए उत्सुक रहता हूं। इसे पढ़ने से मुश्किल मुद्दों को आसानी से समझने में मदद मिलती है। मुझे यह काफी बेहतरीन लगती है। इससे मैं काफी अपडेट रहता हूं।

कस्तूरी

rakeshla143@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003

ईमेल- response-nis@pib.gov.in

जोजिला सुरंग...

भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता का अद्भुत 'ब्रेक-थ्रू'

भारत अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का अब लगातार प्रदर्शन कर रहा है। भारत में सुरंगें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास तक सीमित नहीं हैं। बल्कि ऐसे पर्वत और दुर्गम भूभाग जो कभी संपर्क में बाधा हुआ करते थे, उन्हें भेदकर भौगोलिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा रही है। अटल टनल, चिनाब ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज और बैराबी–सैरांग रेल लाइन निर्माण के बाद अब एशिया की सबसे लंबी 'जोजिला सुरंग' का 9 जून को ऐतिहासिक ब्रेक-थ्रू हुआ। यह ब्रेक-थ्रू केवल निर्माण कार्य की प्रगति नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी दक्षता, इंजीनियरिंग क्षमता और अदम्य संकल्प का प्रतीक है। यह परियोजना जम्मू- कश्मीर और लद्दाख के बीच ऑल-वेदर कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण अध्याय बनकर उभर रही है।

रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से क्षेत्रीय विकास, पर्यटन, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा को गति मिलेगी। इस सुरंग के निर्माण के बाद सोनमर्ग से मिनामर्ग तक की लगभग 2 घंटे की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर बालटाल से मिनामर्ग तक निर्मित की जा रही लगभग 14 किमी लंबाई की जोजिला टनल 6,800 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही है। 2,900 मीटर से 3,310 मीटर की ऊंचाई के बीच इस सुरंग का निर्माण हो रहा है।

भारत का सीफूड निर्यात

करीब 74 हजार करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर

चुनौती भरी वैश्विक बाजार स्थितियों के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 73,890.46 करोड़ रुपये मूल्य का 19.72 लाख मीट्रिक टन सीफूड निर्यात किया गया। यह मात्रा और मूल्य दोनों में उच्चतम स्तर है। इस वर्ष भी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भारतीय सीफूड के प्रमुख आयातक बने रहे। फ्रोजन झींगा प्रमुख निर्यात वस्तु के तौर पर बरकरार रही, जिनसे 49 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ। कुल निर्यात मात्रा में इसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है।

3 करोड़ लखपति दीदी

का लक्ष्य हासिल

देश ने 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब 3 करोड़ और नए लखपति दीदी बनाने के संकल्प को मिशन मोड में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। लखपति दीदी पहल ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी अभियान के रूप में उभरी है। अब प्राथमिकता अतिरिक्त 3 करोड़ महिलाओं को स्थायी एवं विविध आजीविका गतिविधियों से जोड़ने की है, ताकि उनकी आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। देशभर में लगभग 4.11 करोड़ संभावित लखपति दीदियों की पहचान की जा चुकी है, जो अगले चरण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान : देखभाल का एक दशक

देश में सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने की दिशा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 9 जून को 'पीएमएसएमए के 10 वर्ष-देखभाल का एक दशक' थीम के तहत एक राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत की। इस उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए सरकार द्वारा 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया। योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य हर महीने की 9 तारीख को विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसवपूर्व जांच और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना रहा। पिछले एक दशक में इस अभियान के जरिए देश भर में 7.50 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है। इस अभियान ने एक स्वस्थ और सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक बेहद मजबूत नींव रखी है।

पद्म पुरस्कार-2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई, 2026 तक

गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है। नामांकन/सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (**https://awards.gov.in**) पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कार, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। वर्ष 1954 में स्थापित ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, जनसंपर्क, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में विशिष्ट एवं असाधारण उपलब्धियों या सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। सरकार पद्म पुरस्कारों को "जनता का पद्म" बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि सभी नागरिकों से स्व-नामांकन/ सिफारिश करने का अनुरोध किया है।

'भव्य' पोर्टल लॉन्च

देशभर में 100 औद्योगिक पार्क लगाने की प्रक्रिया शुरू

भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। भव्य योजना के अंतर्गत राज्यों को अपनी औद्योगिक क्षमताओं, भूमि की उपलब्धता, निवेशकों की रुचि और क्षेत्रीय संभावनाओं को उजागर करते हुए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य देश भर में 100 औद्योगिक पार्क विकसित करना है ताकि अधिक निवेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके। ये पार्क विभिन्न आकारों में विकसित किए जाएंगे, जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों, छोटे केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में 25 एकड़ से लेकर मध्यम आकार के राज्यों और क्षेत्रों में 100 से 500 एकड़ तक और शहरों एवं कस्बों के निकट 1,000 एकड़ तक के पार्क शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सेवा, साहस और राष्ट्र निर्माण की अनवरत साधना के प्रतीक

10 जून 2026 का दिन भारतीय संसदीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। "राष्ट्र प्रथम" की भावना से प्रेरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनवरत यात्रा ने आज एक नया इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक तिथि को वे 4,399 दिनों की सेवा पूर्ण करते हुए देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए।

इससे पूर्व यह गौरव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जो 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक कुल 4398 दिन इस पद पर आसीन रहे। प्रधानमंत्री मोदी का यह कीर्तिमान केवल दिनों की गणना मात्र नहीं है, यह उस गहरी आस्था और अटूट विश्वास का प्रमाण है, जो भारत के किसानों, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपने प्रधानमंत्री में प्रकट की है।

प्रगति पथ पर अग्रसर... 12 वर्ष की विकास यात्रा एक युग के रूप में स्थापित हो चुकी है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत...आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा, और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग सशक्त करेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रस्ताव

आज 10 जून 2026 का दिन, भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। **आज श्री नरेंद्र मोदी जी, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं।** उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 दिनों की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, 1952 से लेकर 1964 तक, निरंतर 4,398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था।

यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जनविश्वास और जनभागीदारी की शक्ति का प्रतीक है। जब कोई जनप्रतिनिधि राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ जीता है, जब वो सत्य, निष्ठा, परिश्रम, ईमानदारी और जीवन की शुचिता को अपना मार्गदर्शक बनाता है...इन मूल्यों को लेकर निरंतर जनता की सेवा में समर्पित रहता है...तब जनता-जनार्दन उसे अभूतपूर्व समर्थन के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। आज का यह ऐतिहासिक क्षण उसी जन-आशीर्वाद का प्रतिबिंब है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित करती है।

10 जून, 2026 की यह ऐतिहासिक उपलब्धि, कुछ और बड़े पड़ावों के साथ आई है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार के भी 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 वर्ष से निरंतर सेवा का भी ऐतिहासिक पड़ाव पार करने वाले हैं।

ये भी उल्लेखनीय है कि छह दशक बाद, देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार को जनादेश दिया है। **हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व ऐसे कुशल हाथों में है जिनके पास संवेदनशीलता भी है, संयम भी है, नीयत भी है और निर्णायक क्षमता भी है।**

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन सेवा, साहस और राष्ट्र निर्माण की एक सतत साधना का प्रतीक रहा है। एक संगठन कार्यकर्ता और फिर एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके व्यापक अनुभव के कारण जमीनी वास्तविकताओं की उनकी समझ ने, नीतियों को अधिक संवेदनशील, व्यावहारिक और परिणामकारी बनाया है।

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के उपरांत

प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बीते 12 वर्षों में वीमेन लेड डवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा में जुड़ा है।

उनके मार्गदर्शन में सरकार ने हमेशा देश की महिलाओं को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। शौचालय की सुविधा हो, धुआं मुक्त रसोई हो, गर्भावस्था के समय आर्थिक मदद हो, मुद्रा योजना हो, पीएम आवास महिलाओं के नाम होना हो, लखपति दीदी अभियान हो, जन्म से लेकर जीवन के अंतिम पहर तक, जीवन के हर पड़ाव पर देश की महिलाओं के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम विकसित किया गया है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करके, देश के नीति निर्माण में उनकी भागीदारी और बढ़ाने का प्रयास हुआ है।

संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्होंने स्वयं को "प्रधान सेवक" कहा था। उन्होंने देश के संविधान को पवित्र ग्रंथ बताया था और यह भी कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को, सरकार का ध्येय वाक्य बनाते हुए, बीते 12 वर्ष इन्हीं संकल्पों की अभिव्यक्ति रहे हैं।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। देश के करोड़ों लोगों तक पहली बार इतने बड़े स्तर पर पक्के घर, बिजली, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाएं पहुंचीं। पहली बार करोड़ों-करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले, उन्हें बिना किसी बिचौलिए के सरकारी मदद सीधे मिलने लगी। पहली बार 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली और पहली बार 60 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का भरोसा मिला। इन कदमों से देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा और गरिमा के साथ जीवन जीने का विश्वास जागा। इसी का परिणाम रहा कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी को परास्त कर पाए।

प्रधानमंत्री जी, युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। उनके मार्गदर्शन में, कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकॉनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमिता और फिटनेस को अभूतपूर्व बल मिला है। बीते 12 वर्ष में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम बना है और अब हमारा देश दुनिया की एक बड़ी खेल शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। भारत ने मिशन चंद्रयान के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराकर विश्व को अपनी बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता का भी परिचय दिया है।

विकसित भारत के जिन चार स्तंभों की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनमें से एक प्रमुख स्तंभ हमारे किसान हैं। बीते 12 वर्षों में किसानों के लिए नई वैरायटी बीज, अनेकों अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना, पीएम किसान सम्मान निधि देना, MSP में वृद्धि और सरकारी खरीद में वृद्धि, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के लिए अभूतपूर्व काम किए गए हैं। पशुपालकों और मछुवारों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के माननीय पीएम के निर्णय का लाभ लाखों

लोगों को हो रहा है। **आज भारत का कृषि निर्यात बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है। ये माननीय पीएम की किसान कल्याण से जुड़ी नीतियों का ही स्पष्ट प्रभाव है।**

प्रधानमंत्री जी राष्ट्र प्रथम के भाव से बड़े निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटे। यही कारण है कि जो निर्णय, जो रिफॉर्म्स बीते अनेक दशकों से लंबित थे, वो आज सच्चाई बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल-370 को हटाना, GST लागू करना, OROP लागू करना, CDS पद का गठन करना, गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देना, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू करना, CAA कानून बनाना, तीन तलाक के विरुद्ध कानून बनाना, वक्फ कानून में संशोधन करना, परमाणु क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए शांति कानून बनाना, भारतीय न्याय संहिता लागू करना, दर्जनों श्रम कानूनों को 4 कोड्स में समेटना, ऐसे अनेक बड़े फैसले माननीय पीएम की निर्णायक छवि को मजबूत करते हैं।

प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को नया आयाम दिया है, नई बुलंदी दी है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का श्रेय उनके नेतृत्व को ही जाता है। पहली बार, सीमापार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पहली बार, सीमा-पार एयर स्ट्राइक की गई। पहली बार, ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया गया, जो अकल्पनीय थे। माननीय पीएम के निर्देशों के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु नदी समझौते को निलंबित स्थिति में रख दिया है। अब भारत का जल भारत के किसानों के काम आएगा।

माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो रहा है। उत्तर-पूर्व में अनेक स्थाई शांति समझौते किए गए हैं, जिससे वहां अभूतपूर्व शांति स्थापित हो रही है। बांग्लादेश के साथ दशकों से लंबित सीमा विवाद को भी सुलझाया गया है।

प्रधानमंत्री जी का ये दृढ़ विश्वास रहा है कि आत्मनिर्भर हुए बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिली है। आज भारत, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबील, फार्मा, ऐसे अनेक क्षेत्रों में मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथ ही, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नॉलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में भी प्रशंसनीय कार्य कर रहा है।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक भूमिका भी अभूतपूर्व रूप से सशक्त हुई है। वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ को नई प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। जी-20 की सफल अध्यक्षता,

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के क्षेत्र में भी भारत ने विश्व के समक्ष एक जिम्मेदार और प्रेरक मॉडल प्रस्तुत किया है।

भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, **Coalition for Disaster Resilient Infrastructure** और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसी अनेक पहलें की हैं। मिशन **LiFE** और 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसे जनआंदोलनों को प्रधानमंत्री जी ने, वैश्विक मंचों पर भारत के योगदान के रूप में स्थापित किया है। 'कैच द रेन' और अमृत सरोवर जैसे अभियानों ने जल संरक्षण के साथ ही, नौजवान पीढ़ी को इस दायित्व के प्रति जागरूक किया है।

ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को स्वर प्रदान करना, तथा विभिन्न वैश्विक पहलों में भारत की अग्रणी भूमिका ने देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से 170 से ज्यादा देश एकजुट हुए और संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया।

भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। इससे भारत की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। माननीय पीएम ने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, राष्ट्रीय गौरव के पुनर्स्थापन तथा अपनी सभ्यतागत विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया।

आज इसके भी परिणाम देश देख रहा है। नया संसद भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन, ऐसे अनेक निर्माण नए भारत के नए आत्मविश्वास के प्रतीक बने हैं।

प्रधानमंत्री जी ने जनभागीदारी को परिवर्तन का माध्यम बनाया है। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, या फिर LPG सब्सिडी को छोड़ने का आह्वान हो, ये बीते वर्षों में जनता के सामूहिक प्रयासों का बहुत बड़ा माध्यम बने हैं। जनभागीदारी से परिवर्तन की इसी प्रेरणा से देश ने कोरोना जैसी महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया। और वर्तमान में भी एक बहुत बड़े वैश्विक संकट से, 140 करोड़ देशवासी मिलकर सामना कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल यह भी रेखांकित करता है कि पिछले 12 वर्षों में देश को प्राप्त राजनीतिक स्थिरता ने विकास की गति को अभूतपूर्व बल प्रदान किया है। बीते वर्षों में जितनी तेजी से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप बदला है, वो अपने आप में एक मिसाल है। **भारत की राजनीतिक स्थिरता से देश के वैश्विक प्रभाव और वैश्विक निवेशकों पर भी एक सकारात्मक असर हुआ है।**

बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, शासन में गतिशीलता, निर्णयों में पारदर्शिता, और नीतियों में दूरदर्शिता का रहा है। जिससे भारत, विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित होती, बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल

1. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है।
2. गरीब कल्याण एवं वंचित वर्गों के सशक्तीकरण हेतु उनके नेतृत्व में हुए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करता है।
3. उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने, गरीबी को परास्त किया है, इसके लिए माननीय पीएम की नीतियों की सराहना करता है।
4. राष्ट्र सेवा के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है।
5. समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है।
6. राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है।
7. विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।

और साथ ही,

केंद्रीय मंत्रिमंडल, माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल विश्वास व्यक्त करता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत....आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा, और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग सशक्त करेगा। ■

ऐतिहासिक नेतृत्व, वैश्विक सराहना

नया भारत, समर्थ भारत

लोकतांत्रिक नेतृत्व के एक ऐतिहासिक मील के पत्थर को छूते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। इस गौरवपूर्ण अवसर पर वैश्विक नेताओं ने उनके परिवर्तनकारी शासन, समावेशी और सशक्त भारत के विजन तथा 'ग्लोबल साउथ' की मुखर आवाज बनने के लिए वैश्विक मंच से भेजे बधाई संदेश...

भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व भर के नेताओं से बधाई संदेश प्राप्त हुए। बधाई संदेश देते हुए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र, भाई और मार्गदर्शक बताया वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उन्हें हार्दिक बधाई दी और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए श्रीलंका की प्रतिबद्धता को दर्शाया।

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। इसे उनके वर्षों के समर्पित लोक सेवा और नेतृत्व का प्रमाण बताया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के प्रति मलेशिया की प्रतिबद्धता को दोहराया।

नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। लगातार तीन कार्यकालों में भारत की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर जताए गए विश्वास और भरोसे का उल्लेख किया। वहीं केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पीएम मोदी को बधाई दी।

इटली की प्रधानमंत्री, जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने रोम में हुई अपनी हालिया मुलाकात को याद किया। दोनों देशों और उनकी जनता के हित में भारत एवं इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्योंग ने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को बधाई दी।
- डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निरंतर सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर बधाई दी।

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी।

साइप्रस के राष्ट्रपति, निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने पीएम मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी। उन्होंने इस उपलब्धि को वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व का परिणाम बताया।

- ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस, जर्मनी के चांसलर, फ्रेडरिक मर्ज, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी को 'एक रोल मॉडल और लीडरशिप की मिसाल' बताया।

- त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में एक प्रमुख आवाज बनकर उभरा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

अहमदाबाद मेट्रो समेत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी

एनडीए सरकार के 12 साल पूर्ण होने के अवसर पर 10 जून को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। साथ ही इस बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार सहित इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी दी मंजूरी...

निर्णय : अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2ए (कोटेश्वर मार्ग से एयरपोर्ट गलियारे) को स्वीकृति।

प्रभाव : इस गलियारे की लंबाई 6.032 किलोमीटर है। इसमें 5 स्टेशन (4 एलिवेटेड और 1 अंडरग्राउंड) शामिल हैं। चरण 2(ए) के कार्यान्वित होने पर अहमदाबाद-गांधीनगर गलियारे में 77.63 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत, 2,169.04 करोड़ रुपये होगी। कॉरिडोर का उद्देश्य हवाई अड्डे से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। साथ ही उन प्रमुख आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़कर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना है। यह परियोजना बेहतर संपर्क, यातायात जाम की समस्या से निजात, पर्यावरणीय लाभ, आर्थिक विकास और गुणवत्तापूर्ण जीवन का भरोसा बढ़ाती है।

निर्णय : आंध्र प्रदेश के न्यू कैपिटल सिटी, अमरावती में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) के निर्माण को स्वीकृति।

प्रभाव : यह कैपिटल सिटी, अमरावती के साथ-साथ आंध्र प्रदेश में पहली जीपीआरए परियोजना है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पर्याप्त आवासीय सुविधा प्रदान करके केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ कम करना है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों के निकट रहने की सुविधा प्रदान करके, यह परियोजना कुशल सरकारी कामकाज में सहयोग करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। परियोजना की अनुमानित लागत 1,234.91 करोड़ रुपये है। अनुमान है कि निर्माण चरण में प्रति वर्ष लगभग 7 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होंगे।

निर्णय : आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी अमरावती में नए केंद्रीय सरकारी जनरल पूल कार्यालय के निर्माण को मंजूरी।

प्रभाव : यह परियोजना अमरावती के नए ग्रीनफील्ड शहर में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसे विश्व स्तरीय शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए ऑफिस अकोमोडेशन की बढ़ती मांग को पूरा करना है, ताकि उन्हें एक ही छत के नीचे लाया जा सके। इस एकीकरण से अंतर-विभागीय समन्वय बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होगा। निर्माण चरण के दौरान प्रति वर्ष लगभग 7 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,299.08 करोड़ रुपये है। ■

मंत्रिमंडल के फ़ैसले पर प्रेस ब्रीफ़िंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

आवरण कथा
न्याय संहिता के 2 वर्ष

स्वदेशी न्याय व्यवस्था

नई सुबह, नई दिशा

न्याय एक शब्द भर नहीं, बल्कि विशालता समेटे हुए सभ्य समाज की नींव है। इसी सोच के साथ पहली जुलाई 2024 को भारत ने गुलामी की मानसिकता वाले औपनिवेशिक काल के उन तीन कानूनों को विदा किया, जो डेढ़ सौ वर्षों से दंड देने के मूल सिद्धांत पर आधारित था। दो वर्ष पूर्व भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पूर्ण स्वदेशीकरण के साथ 'दंड की जगह न्याय के नए युग' की शुरुआत की। दो सदी की दूरी तय करते हुए 21वीं सदी में भारत को गुलामी की छाया से मुक्त अपना कानून मिला। इसी का परिणाम है कि नागरिक हों या पुलिस और अदालतें, बीते 2 वर्षों में न्याय की किताब और भाषा दोनों बदल गई है। इस नए बदलाव से भारत का जन-जन देख रहा है स्वदेशी न्याय व्यवस्था का नया सूर्योदय...

1. चंडीगढ़ में वाहन चोरी के एक केस में एफआईआर के बाद, 2 महीने 11 दिन में अदालत ने सजा सुना दी। क्षेत्र में अशांति फैलाने के एक और आरोपी को अदालत ने सिर्फ 20 दिन में पूरी सुनवाई के बाद सजा सुना दी।

2. दिल्ली में एक केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक केवल 60 दिन का समय लगा और आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई।

3. बिहार के छपरा में भी एक हत्या के मामले में एफआईआर से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने में महज 14 दिन लगे। त्वरित न्याय मिलने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

नए कानून पूरी तरह से सभी राज्यों में अमल में लाने की सीमा 3 साल रखी गई है, लेकिन बीते 2 वर्ष में ही इस बदलाव को मिल रही सफलता संतोष देने वाली है। यह चंद उदाहरण ही बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की ताकत क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं। यह बदलाव दिखाता है कि जब कोई सरकार सामान्य नागरिकों के हितों के प्रति समर्पित होती है, ईमानदारी और निष्ठा से जनता की समस्याओं को दूर करना चाहती है, तो ऐसे ही त्वरित परिणाम आते हैं। इसी का परिणाम है कि आज नया भारत, न्याय का नया युग देख रहा है। देश का नागरिक आज यह महसूस कर रहा है कि 'दंड नहीं, न्याय सर्वोपरि' है और नए भारत का नया कानून अब उसे न्याय देने के लिए है। आजाद भारत की अपनी तीन ऐतिहासिक कानूनों ने न्याय का स्वरूप बदल दिया है जो अब 'नागरिक प्रथम-न्याय प्रथम' के सिद्धांत पर आधारित हैं। यह पूर्ण रूप से नागरिक केंद्रित, सुगम और भारतीय मूल्यों पर आधारित हैं।

भारतीयता के भाव से भरे तीनों नए कानून डिजिटल प्रक्रिया के साथ समयबद्ध न्याय के प्रतीक बन गए हैं। बीते 2 वर्ष की ही सफलताओं को देखें तो अप्रैल 2026 तक भारतीय न्याय संहिता के तहत 63 लाख से अधिक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज हुई, जिसमें से लगभग 52 लाख में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट सौंप दी गई। इतना ही नहीं, 60 दिन की अवधि में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट सौंपने की दर पूर्व के कानून के समय 50 प्रतिशत के आसपास थी, जो बीते 2 वर्ष में नए कानून के कारण 61 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। जिन मामलों में 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना होता है, उसकी दर पुराने कानून के समय लगभग 39 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 51 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। जीरो एफआईआर की संख्या भी इन 2 वर्षों में 60 हजार के करीब पहुंच गई है। यौन अपराध जैसे संवेदनशील मामले में कानून में बदलाव का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। पुराने कानून के समय 2018 में यौन अपराधों में दो महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की अनुपालना दर 44 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 71 प्रतिशत पहुंच गई है। फॉरेंसिक क्षमता का विस्तार तेजी से हुआ है।

समयबद्ध न्याय अब पहली कसौटी

न्याय की पहली कसौटी है- समय से न्याय मिलना। आपने सुना होगा- Justice delayed, Justice denied... यानी न्याय में देरी, न्याय नहीं मिलने के समान होता है। इसलिए भारतीय न्याय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक है। सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों से एक नए युग की शुरुआत है। यह सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए त्वरित न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसमें जल्दी चार्जशीट फाइल करने और जल्दी निर्णय सुनाने को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी केस में हर चरण को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है क्योंकि भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है- नागरिक प्रथम। जीरो एफआईआर को मजबूती से कानूनी रूप दिया गया है। इस नए कानून का एक और मानवीय पक्ष है कि बिना सजा के लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अब तीन साल से कम सजा वाले अपराध के मामले में गिरफ्तारी भी उच्च प्राधिकारी की सहमति से ही हो सकती है। छोटे अपराधों के लिए अनिवार्य जमानत का प्रावधान किया गया है। साधारण अपराधों में सामुदायिक सेवा का विकल्प भी रखा गया है जो आरोपी को समाज हित में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का नया अवसर देगा। पहली बार के अपराधियों के लिए भी न्याय संहिता संवेदनशील है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हर पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। भारतीय न्याय संहिता ये सुनिश्चित करती है कि कानून पीड़ित के साथ खड़ा हो। चार्जशीट से लेकर फैसला सुनाने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद जेलों से ऐसे हजारों कैदियों को छोड़ा गया है, जो पुराने कानूनों की वजह से जेल में बंद थे। यह सिद्ध करता है कि एक नई व्यवस्था, नया कानून नागरिक अधिकारों के सशक्तीकरण को कितनी ऊंचाई दे सकता है।

लोकतंत्र की मूल भावना हुई पुनर्स्थापित

विकसित भारत के संकल्प की ओर अग्रसर राष्ट्र के लिए इन कानूनों की जरूरत को समझिए। देश 1947 में आजाद तो हुआ, लेकिन अंग्रेजी काल में बने कानून कायम रह गए। जबकि यही कानून अंग्रेजों के अत्याचार-शोषण का जरिया थे। यह कानून तब बनाए गए थे, जब अंग्रेजी सत्ता भारत पर अपना शिकंजा बनाए रखने के

न्यायिक सुगमता का नया युग

19वीं सदी में बने अंग्रेजी शासनकाल के कानूनों से मुक्ति मिली। 21वीं सदी के सबसे बड़े रिफॉर्म के बाद भारत को अपना कानून मिला है। जिसमें है- न्याय, समानता और निष्पक्षता का मूल मंत्र। सही अर्थों में यह नए भारत की आत्मा एवं संविधान के सिद्धांतों का प्रकटीकरण है...

दंड नहीं, न्याय देना उद्देश्य

- 150 वर्ष पुराने अंग्रेजी काल में बने कानूनों से आजादी।
- इन कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद देशभर में किसी भी **FIR** में सुप्रीम कोर्ट तक लगभग 3 साल में न्याय मिलेगा।
- नए कानूनों में जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने, चार्ज फ्रेम करने और जजमेंट देने का समय भी तय।
- 7 साल और उससे अधिक सजा वाले हर अपराध में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है।

आतंकवाद, संगठित अपराध पर सख्ती

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में संगठित अपराध, आतंकवाद पर सख्ती का प्रावधान किया गया है।

लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। यह इसलिए भी हुआ था क्योंकि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। देश के हर कोने में चुनौती पैदा कर दी थी। इसके जवाब में अंग्रेज 1860 में आईपीसी और फिर कुछ साल बाद सीआरपीसी लेकर आए। यह तीनों कानून देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, बल्कि अंग्रेजी राज की सुरक्षा के लिए बने थे। उस समय कानून किस सोच से बने थे, उसका उदाहरण उसके नंबरों से भी मिलता है। उस कानून में हत्या, महिला के साथ अत्याचार जैसे जघन्य अपराधों से पहले सरकारी खजाने की लूट, रेलवे पटरी उखाड़ने की सजा, ब्रिटिश ताज के अपमान को ऊपर रखा गया था।

यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि आजादी के बाद लंबे समय तक भारतीय कानून उसी दंड संहिता के इर्द-गिर्द घूमते रहे। समय-समय पर इनमें सुधार तो हुए लेकिन मूल चरित्र वही बना रहा। अंग्रेजी काल में बने कानूनों की जो आत्मा है, उनका केंद्र बिंदु अंग्रेजी शासन को मजबूत करने की दृष्टि से बनाए गए थे। उस औपनिवेशिक शासन की रक्षा के लिए बनाए गए थे। जिसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा, तब न्याय संहिता में बदलाव उस दिशा में एक निर्णायक कदम बना। अमृत काल में भारत को विकसित बनाने के विराट संकल्प के साथ-साथ गुलामी की सभी निशानियों से मुक्ति की ओर अग्रसर राष्ट्र ने जुलाई 2024 में भारतीय न्याय संहिता बनाकर दूरगामी पहल की। इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में अंग्रेजों की संसद द्वारा पारित किए गए। अब इंडियन पीनल कोड-1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्थापित हो चुकी है।

अब तीनों नए कानून दंड केंद्रित नहीं, बल्कि न्याय केंद्रित आपराधिक न्याय प्रणाली के आधार बन गए हैं। जब न्याय की बात होती है तो न्याय बहुत बड़े समुदाय के प्रति होता है जिसमें आरोपी और पीड़ित दोनों आ जाते हैं। लेकिन दंड कहने पर केवल आरोपी की तरफ ही देखा जाता है। लेकिन अब 'ईज ऑफ जस्टिस' को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही को प्रक्रिया के माध्यम से साकार किया गया है। आज तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आत्मा का प्रकटीकरण है। सही अर्थों में आजादी के इतने दशकों के बाद पहली बार तीनों आपराधिक कानूनों से न्याय प्रणाली का

कर्तव्य पथ पर झांकी... दंड से न्याय की ओर

> *21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन नए कानून हैं। Citizen First, Dignity First और Justice First के मूल मंत्र नए आपराधिक कानूनों के आधार हैं। आज हमारी पुलिस डंडे की जगह डाटा और थर्ड डिग्री की जगह साइंटिफिक एविडेंस पर काम कर रही है।*
>
> **-अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

मानवीयकरण हुआ है। यह न्याय संहिता आज लोकतंत्र की मूल भावना- 'जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए' को सशक्त कर रही है। आजाद भारत की अपनी न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है। अक्सर कहा जाता है कि कानून की नजर में सब एक समान होते हैं, लेकिन व्यावहारिक सच्चाई कुछ और ही थी। गरीब-कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था। कोर्ट-कचहरी-थाने में कदम रखने से डरता था। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदल रही है। उसे भरोसा होने लगा है कि देश का कानून समानता की गारंटी है। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा संविधान में दिलाया गया है।

जन-जन में सुरक्षा का भाव हुआ मजबूत

किसी भी देश की असली शक्ति वहां के लोग होते हैं, और लोगों को शक्ति मिलती है देश के कानून से। इसी वजह से लोग सीना तानकर कहते हैं कि वे कानून का पालन करते हैं। कानून के प्रति नागरिकों की यह निष्ठा राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। कोई भी नियम या कानून तभी प्रभावी होते हैं जब वह समय के मुताबिक प्रासंगिक हों। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। अपराध और अपराधियों के तरीके बदल गए हैं। ऐसे में 19वीं सदी की कोई व्यवस्था व्यावहारिक नहीं हो

डिजिटल प्रक्रिया के साथ समयबद्ध न्याय

नए कानून के 2 वर्ष, उपलब्धियां

समय सीमा + तकनीक = भरोसा

60 दिन में चार्जशीट/Final Report अनुपालन दर

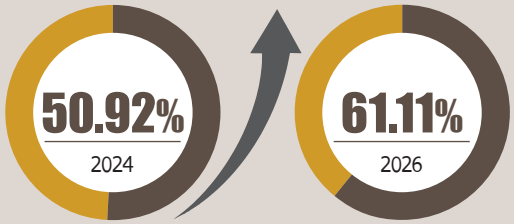

90 दिन में चार्जशीट/Final Report अनुपालन दर

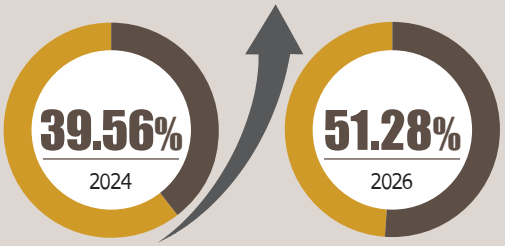

BNS के तहत **FIR**
63.08 लाख

चार्जशीट/**Final Report**
51.95 लाख

35.06 लाख
ई-साक्ष्य के माध्यम से साक्ष्य **ID** निर्मित

59,572 कुल **Zero FIR** दर्ज

1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़े

सकती। इसलिए इन कानूनों को भारतीय बनाने के साथ आधुनिक भी बनाया गया है। अब डिजिटल साक्ष्य भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में रखे गए हैं। जांच के दौरान सबूतों से कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। अब कोर्ट और पुलिस की तरफ से सीधे फोन पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन दिए जा सकते हैं। गवाह के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। डिजिटल साक्ष्य कोर्ट में मान्य हैं और न्याय का आधार बन रहे हैं। इससे अपराधी के पकड़े जाने तक अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा। यह बदलाव देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी थे। डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकों के समन्वय से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। नए कानूनों में आतंकी या आतंकी संगठन कानून की जटिलताओं का फायदा नहीं उठा सकते।

इन कानूनों से हर विभाग की कार्य क्षमता और बढ़ी है। साथ ही, देश की प्रगति को भी गति मिल रही है। कानूनी अड़चनों के दूर होने से भ्रष्टाचार कम हुआ है। इसका प्रभाव निवेश पर भी पड़ रहा है। पहले निवेशक भारत में इसलिए निवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि कोई

यौन अपराधों में दो महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की अनुपालन दर

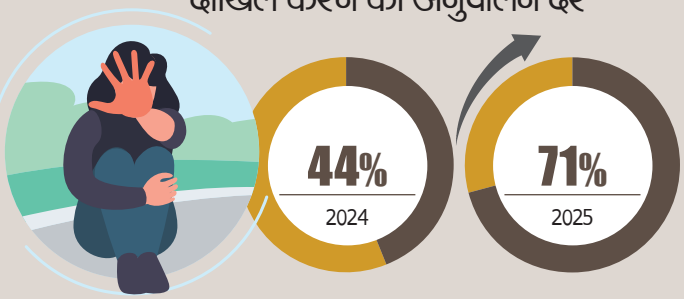

फॉरेंसिक क्षमता-विस्तार

16 **NFSU** प्रस्तावित/संचालित
9 स्थापित + 7 अतिरिक्त स्वीकृत

15 **CFSL** प्रस्तावित/संचालित
7 स्थापित + 8 अतिरिक्त स्वीकृत

7+ वर्ष
की सजा वाले गंभीर अपराध फॉरेंसिक विशेषज्ञ की भूमिका को अनिवार्य/महत्वपूर्ण आधार

> *नए आपराधिक कानूनों में पहली बार आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। साथ ही पुलिस, न्यायपालिका और अभियोजन तीनों के लिए समय सीमा का निर्धारण भी पहली बार किया गया है। पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन और फॉरेंसिक के पांचों स्तंभों को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है।*
>
> **–अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

मुकदमा हुआ तो उसी में वर्षों निकल जाएंगे, यह डर खत्म हुआ है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

विराट मंथन से बनी आजाद भारत की अपनी संहिता

संविधान के 75 वर्ष होने के अवसर पर 1 जुलाई 2024 को संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रारंभ होना एक बड़ी शुरुआत बनकर आया। यह संविधान के आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस प्रयास था। देश की नई न्याय संहिता अपने आपमें जितना समग्र दस्तावेज है, उसे बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है।

इस कानून में भारतीयता की आत्मा बसाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2019 से ही सलाह-मशविरे की व्यापक प्रक्रिया चलाई गई। इसमें सभी उच्च न्यायलयों के मुख्य न्यायधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों, विधि से जुड़े विश्वविद्यालयों, सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों सहित विद्वतजनों और आम नागरिकों से चर्चा की गई। बेजबरूआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलीमथ समिति, माधव मेनन समिति और गृह मामले की संसद की स्थायी समिति के वर्ष 2011, वर्ष 2005 और वर्ष 2006 की 111वीं रिपोर्ट, 110वीं रिपोर्ट, 146वीं रिपोर्ट और सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों-सांसदों, न्यायधीशों, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और विधि विवि से आए सुझावों पर विचार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं एक-एक पंक्ति को पढ़कर कानून का ढांचा खड़ा किया। संसद द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इस कानून को लागू करने के लिए व्यापक स्तर पर

नए कानूनों में कहीं घटाई

तो कहीं बढ़ाई गईं धाराएं

केंद्र सरकार ने नए आपराधिक न्याय सुधार कानूनों में प्राथमिकता को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। क्योंकि आईपीसी 163 सालों से, सीआरपीसी 125 सालों से और एविडेंस एक्ट 150 साल पहले जो ब्रिटिश संसद ने बनाए थे, उसी से चल रहे थे। भारतीय न्याय संहिता में महिला, बच्चे और राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों से जुड़ी धाराओं को सबसे आगे रखा गया है जो औपनिवेशिक युग के कानूनों के विपरीत है। पुराने कानून में राजद्रोह और राजकोष की लूट, शासन के अधिकारियों पर हमले से जुड़ी धाराओं के पहले रखा गया था।

358 धाराएं अब भारतीय न्याय संहिता में हैं। इससे पूर्व भारतीय दंड संहिता, 1860 में 511 धाराएं थीं।

21 नए अपराध की धाराएं जोड़ी गई हैं।

41 धाराओं में कारावास की सजा बढ़ाई गई है।

82 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है तथा 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा की शुरुआत की गई है।

19 धाराओं को खत्म किया गया। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है।

जन-जागरण अभियान चलाए गए, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक आजाद भारत के अपने कानून से परिचित हो सके।

आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां आईं, उन पर मंथन किया गया। सभी कानून का व्यावहारिक पक्ष और भविष्य के मापदंड पर उसे कसा गया। इस समुद्र मंथन जैसी प्रक्रिया से अमृत काल में भारतीय न्याय संहिता की अमृत धारा निकल कर आई। इस विराट सहयोग से बनी भारत की न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध हो रही हैं। पहली जुलाई 2024 से इन कानूनों के लागू होने से ब्रिटिश राज और ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिह्न समाप्त करके संपूर्ण भारतीय कानून लागू कर

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

531 धाराएं हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में 484 थीं। 14 धाराएं निरस्त की गई है।

177 प्रावधानों में किया गया है बदलाव। इसमें नौ नई धाराओं के साथ-साथ 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं।

44 नए स्पष्टीकरण और व्याख्याएं जोड़ी गई हैं।

35 धाराओं में समयसीमा जोड़ी गई है।

35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

170 प्रावधान हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 167 थे।

24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। दो नई धाराएं और छह उप धाराएं जोड़ी गई हैं। छह धाराओं को हटा दिया गया है।

कानून में आहत करते थे ये शब्द

30 जून 2024 तक देश में लागू कानून में ऐसी शब्दावली थी जो आजाद भारत की आत्मा को आहत करते थे लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी वही कानून लागू थे। ये शब्द- **'United Kingdom'** की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, **'Crown'** के प्रतिनिधि, **'London Gazette'**, **'Jury'**, **'United Kingdom of Great Britain and Ireland'**, **'Her Majesty** सरकार', **'London Gazette'** द्वारा निहित की गई प्रक्रियाएं, **'British Crown'** का अपमान, **'England'** के न्यायालय की परंपरा और **'Her Majesty Romanian' 'barrister'** थे जिसका उल्लेख था।

दिए गए। यह भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत बनकर उभरा। इस कानून के सम्पूर्ण रूप से अमल में आने के बाद 'तारीख पे तारीख' का जमाना समाप्त हो जाएगा। अब तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल जाए, ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अन्दर स्थापित हो चुकी है।

पिछले 2 वर्षों में भारत के नए कानूनों ने न्याय की पूरी तस्वीर बदल दी है, जिसका सीधा असर अब देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई 'भारतीय न्याय संहिता' ने न्याय की एक नई शुरुआत की है, जो आज के बदलते भारत की सोच को दिखाती है। ■

1 जुलाई, 2026 से विकसित भारत – जी राम जी लागू

ग्रामीण भारत में अब 125 दिन की रोजगार गारंटी

किसी भी विकासशील राष्ट्र या यूं कहें कि ग्रामीण भारत में आजीविका के लिए कम से कम 125 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इसी विजन से कोविड-19 के संकट में गरीब कल्याण रोजगार गारंटी अभियान भी 125 दिन चलाया था। इसी दूर दृष्टि से तैयार 'विकसित भारत – जी राम जी' कानून 1 जुलाई से लागू हो गया है, इसने मनरेगा की जगह ली है। जी राम जी में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम की मांग करेंगे, उन्हें हर वित्तीय वर्ष में दी जाएगी 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी...

भारत जैसे विकसशील देश में ग्रामीण भारत के विकास के बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। यही वजह है कि संवेदनशील और चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे सयम तक शासन का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत के विकास के लिए बीते 12 वर्षों से लगातार योजनाएं जमीन पर उतार रहे हैं। मार्च, 2020 में जब कोविड-19 की वैश्विक महामारी में लॉकडाउन घोषित किया गया तो 1.75 लाख करोड़ रुपये का विशेष गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया। फिर गांवों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों को रोजगार और आजीविका का व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कर 50 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं लागू कीं। गरीबों को गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली देने की उनकी सोच का ही परिणाम है कि अब विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) में भी 125 दिन की मांग आधारित रोजगार की गारंटी दी गई है। यह नया कानून ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक ब्लूप्रिंट है जो 1 जुलाई से लागू हो गया है।

विकसित भारत- रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी कानून भारत की ग्रामीण रोजगार

विकसित भारत जी राम जी के प्रमुख बिंदु...

- एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के लिए मजदूरी रोजगार गारंटी को मनरेगा में प्रति वर्ष 100 दिन से बढ़ाकर नए कानून में 125 दिन किया गया है।
- इस कानून के तहत मनरेगा में व्यापक वैधानिक बदलाव कर उसे रिप्लेस किया गया है जो जवाबदेही, बुनियादी ढांचे के परिणामों और आय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है।
- ग्राम सभा, इस अधिनियम के तहत किए गए सभी कार्यों की मॉनिटरिंग करेगी। इसके लिए ग्राम पंचायत सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएगी।
- निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में श्रमिक बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार होंगे।
- मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर डीबीटी के माध्यम से सीधे श्रमिकों के खातों में किया जाएगा।
- समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार श्रमिक विलंब क्षतिपूर्ति (मुआवजा) पाने के पात्र होंगे।
- वर्तमान ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक विकसित भारत-जी राम जी के अंतर्गत मान्य रहेंगे।
- केवल ई-केवाईसी लंबित होने के कारण किसी भी श्रमिक को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा।
- चालू वित्त वर्ष में 1,51,282 करोड़ से रुपये अधिक की राशि नए कानून में रोजगार पर खर्च होंगे जिनमें केंद्रीय हिस्से के लिए 2026-27 के बजट में 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह बजट अनुमान में ग्रामीण रोजगार में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है।
- जल सुरक्षा एवं जल से संबंधित कार्य किए जाएंगे जिसमें सिंचाई, जल निकायों का पुनरुद्धार, पौधरोपण, नहर, बाढ़ जलमार्ग, भूमिगत बांध निर्माण, तालाब, कुएं का निर्माण, सामुदायिक जल भराव भूमि का सुधार शामिल हैं।
- मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम होंगे जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा, सामुदायिक सुविधा से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।
- आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, कौशल, उद्यम विकास से संबंधित काम होंगे। ग्रामीण हाट, साप्ताहिक बाजार, खाद्य एवं कृषि भंडारण, नर्सरी की खेती बढ़ाना, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन शामिल है।
- निगरानी के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणन, जियो रेफरेंसिंग, उपग्रह चित्रण, कार्यों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। ऐसा मोबाइल एप जिसमें डैशबोर्ड आधारित मॉनिटरिंग तंत्र हो और रीयल टाइम पर मांग, कार्य, श्रमिकों को काम पर लगाने, प्रगति सब कुछ देखा जा सके।

नीति में एक निर्णायक बदलाव का आधार बनेगा। इस कानून में एक आधुनिक, जवाबदेह और इंफ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित ढांचे के माध्यम से मनरेगा की कमियों को दूर किया गया। वीबी-जी राम जी ग्रामीण भारत में गारंटीकृत रोजगार का विस्तार करेगा, राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं और कार्यों के बीच ताल-मेल बिठाएगा क्योंकि इसमें मजबूत डिजिटल शासन की व्यवस्था जोड़ी गई है। ग्रामीण रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और गांवों में आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी। ग्राम पंचायतों को ग्रामीण परिवर्तन के केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित करते हुए यह कानून सशक्त, समृद्ध और विकसित ग्रामीण भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनेगा। यह नई ग्रामीण रोजगार गारंटी विकसित भारत 2047 का सारथी बनने में विकसित ग्रामीण भारत का सपना भी साकार करेगा। ■

कुशल भारत की ओर मजबूती से बढ़ते कदम

हर देश के पास अलग सामर्थ्य होता है लेकिन इसे उपयोग में लाने के लिए युवा शक्ति की जरूरत होती है। युवा शक्ति जितनी सशक्त होती है देश उतना ही विकास करता है। इस कड़ी में स्किल इंडिया मिशन एक मजबूत स्तंभ बना है, जिसने जमीनी स्तर पर युवाओं को बहुत ताकत दी है। 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ यह मिशन एक ऐसा परिवर्तनकारी पहल बनकर उभरा है जिसने बीते 11 वर्षों में देश भर के लाखों लोगों को बनाया है कुशल और सशक्त...

त्रिपुरा के दूरदराज के गांव की रहने वाली आदिवासी नित्या देवी निहोतिया ने स्किल इंडिया मिशन के जरिए रबड़ बागान कार्य में प्रशिक्षण लिया और एक नर्सरी की शुरूआत की। इस नर्सरी के जरिए अब निहोतिया को 4,000 रुपये प्रति माह का मुनाफा होता है। इस योजना की लाभार्थी निहोतिया कहती हैं कि सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो कई समस्याओं का निदान हो जाता है। ऐसी ही एक और कहानी दो बहनों पूनम और कोमल की है। इनकी भी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि ये लोग अपनी शिक्षा भी जारी नहीं रख पाए थे। ऐसे में इनके लिए स्किल इंडिया एक उम्मीद की किरण बनकर आया। दोनों बहनों ने कौशल प्रशिक्षण लिया। अब दोनों बहनें कपड़ा कंपनी के कर्मचारी के रूप में काम कर रही हैं। अब वे न केवल अपने परिवारों का सहयोग करती हैं बल्कि उन महिलाओं के लिए एक आदर्श मॉडल बन गई हैं जो अपने कौशल के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं। आज नित्या देवी, पूनम और कोमल उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा किया और अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं।

नित्या देवी निहोतिया

पूनम और कोमल

15 जुलाई 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल भारत मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत, भारतीय युवाओं के लिए उनके पेशेवर कौशल को और बेहतर तरीके से पॉलिश करने का सर्वोत्तम मंच मिला। मिशन का उद्देश्य भारत भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, युवाओं को अच्छी तरह से कौशल युक्त बनाना है। भारत सरकार का यह कदम मील का पत्थर साबित हुआ और इस योजना ने उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण के साथ लाखों भारतीय युवाओं को जोड़ने एवं उन्हें

मिशन के तहत निम्नलिखित योजना शामिल

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
- जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

1.64 करोड़ उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई के तहत, मार्च 2026 तक 35 से अधिक क्षेत्रों में किया गया प्रशिक्षित

- निर्माण, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों और करियर एवं शिक्षा परामर्शदाता पदों के लिए 3.15 लाख से अधिक उम्मीदवारों को किया गया प्रशिक्षित
- अभी, पीएमकेवीवाई 4.0 में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं
- पीएमकेवीवाई 4.0 ने 31 मार्च 2026 तक 36 राज्यों और 737 जिलों को कवर करते हुए 38 क्षेत्रों में 27.24 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

- वर्तमान में, 294 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) कार्यरत।

36,48,69 लाभार्थी 2018 से 31 मार्च 2026 तक किए गए प्रशिक्षित

- पाठ्यक्रम स्थानीय मांग के अनुरूप हैं जिनमें सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं शामिल।
- 31 मार्च 2026 तक 26,720 जनजातीय लाभार्थियों को नामांकित किया गया है और 26,519 को प्रशिक्षित किया गया है।

> *कौशल भारत हमारे युवाओं को कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को मजबूत कर रहा है।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)

- अगस्त 2016 में शुरू की गई यह योजना वर्तमान में अपने दूसरे चरण, एनएपीएस 2.0 में लागू की जा रही है।
- सरकार एनएपीएस पोर्टल के माध्यम से सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में 25 प्रतिशत वजीफा (1,500 रुपये प्रति माह तक) का योगदान देती है।
- 2016 से 31 मार्च, 2026 तक ऑटोमोटिव, आईटी-आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, खुदरा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में 54.41 लाख से अधिक प्रशिक्षु लगे हुए हैं।
- वित्त वर्ष 2025-26 में, लगभग 12.35 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, लगभग 6.42 लाख प्रशिक्षुओं ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपना ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण पूरा किया।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

- सीटीएस के तहत, देश भर में 14,688 आईटीआई (सरकारी - 3,345 और निजी - 11,343) के माध्यम से 169 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
- मार्च 2026 तक, कुल 14 सीटीएस पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं और तीन साल की अवधि में 22 मौजूदा पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया है।
- आईटीआई में नामांकन वित्त वर्ष 2022-23 में 12.51 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 14.70 लाख हो गया है।

सशक्त बनाने में मदद किया। साथ ही उनके लिए इस प्रशिक्षण ने बेहतर आजीविका के लिए द्वार खोल दिए।

इस योजना के संभावित विकास पाठ्यक्रमों ने महिलाओं के लिए भी अद्भुत काम किया। महिलाओं को आजीविका अर्जित करने के लिए इस योजना में प्रशिक्षित किया गया। एक छोटे से प्रशिक्षण ने इन महिलाओं के जीवन को बदल दिया या कहें कि अब ये साधारण महिलाएं, खुद हीरो बन चुकी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ■

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 11 वर्ष

तकनीक से परिवर्तन का नया युग

आज हर नागरिक के जीवन का प्रौद्योगिकी अभिन्न अंग है। सामाजिक सशक्तीकरण, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, स्वास्थ्य हो या परिवहन-लॉजिस्टिक हर स्तर पर देश में पिछले एक दशक में डिजिटलीकरण बढ़ा है। इन सबके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण और नागरिकों को सशक्त बनाने की सोच है। इसी सोच के साथ 1 जुलाई 2015 को शुरू डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से नागरिकों के जीवन में सुगमता बढ़ी है तो डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की 11वीं वर्षगांठ पर करते हैं इसकी प्रगति पर चर्चा...

भारत में डिजिटल समावेशन केवल उपकरण और डेटा तक सीमित नहीं है, यह क्षमताओं का विकास करने, अवसर सृजित करने और हर गांव तथा नगर तक विकास पहुंचाने का सेतु बन गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू होने के बाद से देश में कनेक्टिविटी को कौशल विकास, प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप के साथ जोड़कर, भारत में समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया है। डिजिटल इंडिया ने डिजिटल शासन को मजबूती दी है जिससे न सिर्फ जीवन में सुगमता बढ़ी है बल्कि व्यापार करना भी आसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने अनेक पड़ाव पार किए हैं। अनेकों महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं तो अब अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत का मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है।

देश ही नहीं दुनिया ने भी जनधन-आधार-मोबाइल की त्रिशक्ति को देखा है। बैंकिंग सिस्टम को नए स्तर पर पहुंचाया है तो डिजिटल इंडिया की इस ताकत ने 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी खजाने की लीकेज को रोकने का काम किया है। इसी तरह भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की दुनिया के रीयल टाइम पेमेंट में 49% की भागीदारी हो चुकी है। नौ देश भारत के इस सिस्टम को अपना रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर हो या फिर डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग, इसने रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित किए हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2029-30 तक राष्ट्रीय आय में पांचवें हिस्से के बराबर योगदान करेगी।

> *भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आज पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन चुका है। हम नेक्स्ट जेनरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को नेक्स्ट फेज में पहुंचा दिया है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स करने वाला देश बना है।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

इस तरह जीवन सुगम बना रहा है डिजिटल इंडिया

सामाजिक सशक्तीकरण

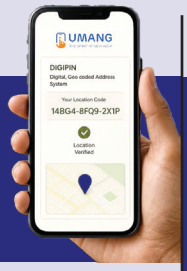

11+ करोड़ उमंग एप पर पंजीकरण हैं, जहां से नागरिक करीब 2,400 तरह की सरकारी सेवाएं ले सकते हैं।

- 6+ करोड़ उपयोगकर्ता हैं **MyGov** वेबसाइट पर।
- 2+ करोड़ युवा और संगठन **MyBharat** पोर्टल से जुड़े हैं, 783 जिलों में माईभारत केंद्र स्थापित होंगे।
- 7.22 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारतनेट योजना में, देशभर में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत हुई है।
- 2+ लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट कार्यक्रम के तहत ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

70+ करोड़

डिजिलॉकर उपयोगकर्ता हैं जिसमें 950 करोड़ डिजिटल दस्तावेज हैं।

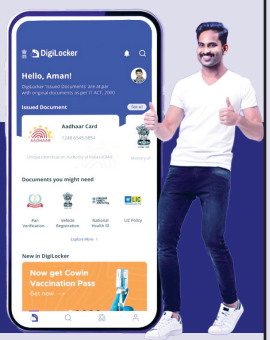

- 74.4 करोड़ से अधिक प्रयोगकर्ता हैं मेरी पहचान वेबसाइट पर, जहां से 16 हजार से अधिक सेवाएं जुड़ी हैं, सिंगल साइनइन से अनेक सरकारी सेवाएं यहां ली जा सकती हैं।
- 5+ लाख कॉमन सर्विस सेंटर देशभर में काम कर रहे हैं, जहां सहायक डिजिटल मोड में 800 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं।
- 90% से अधिक फाइलें ई-ऑफिस में आ चुकी हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में पेपरलेस कामकाज को मुमकिन बनाया है।

वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन

188+ करोड़

ई-वे बिल 2025-26 में जनरेट हुए, परिवहन के लिए कई राज्य-स्तरीय परमिट के स्थान पर एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है।

- 10+ करोड़ से अधिक बार डिजि यात्रा का उपयोग देश के 38 हवाई अड्डों पर किया जा चुका है।
- 51+ लाख करोड़ रुपये जनधन-आधार-मोबाइल की त्रिशक्ति से डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जा चुके हैं
- 58+ करोड़ जनधन खाता बने।
- 144+ करोड़ से अधिक आधार नंबर जारी, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली है। 2014 में 61 करोड़ आधार थे।
- 9 देशों ने अपनाया भारतीय यूपीआई।
- भारतीय यूपीआई को सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, कतर और श्रीलंका के साथ अब कंबोडिया में भी स्वीकार किया जाता है।
- 49% है यूपीआई के माध्यम से वैश्विक रीयल टाइम भुगतान में भारत की हिस्सेदारी।
- 81% से अधिक हिस्सेदारी है यूपीआई की भारत के सभी खुदरा डिजिटल लेनदेन में।
- 64+ करोड़ लोग और व्यापारी यूपीआई प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स

16+ लाख करोड़ रुपये

के अनुमानित लागत वाले 352 प्रोजेक्ट का पीएम गतिशक्ति प्लेटफार्म पर इवैल्यूएशन किया जा चुका है।

- 12+ करोड़ फास्टैग जारी, टोल प्लाजा पर अब कुछ सेकेंड रुकती हैं गाड़ियां, ईंधन खर्च घटा-पर्यावरण को भी फायदा।
- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) एक डिजिटल प्लेटफार्म है जो लॉजिस्टिक्स संबंधित मंत्रालय और विभागों के डेटा को एक ही प्लेटफार्म पर एकत्रित करता है।

स्वास्थ्य सेवा एवं कल्याण

- 90+ करोड़ आभा खातों की संख्या का रिकॉर्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने बनाया, यह 14 अंक की स्वास्थ्य पहचान संख्या है।
- 45+ करोड़ ई-कंसल्टेशन ई-संजीवनी से हुए।
- 8.9 करोड़ लाभार्थी और 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी पोषण ट्रैकर से जुड़े।
- आरोग्य सेतु एप ने कोविड-19 के दौरान टीकाकरण और उसकी पहचान में खूब सहायता की।

किसान और ग्रामीण

4.27+ लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पीएम किसान में दी जा चुकी है। यह किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ओटीपी आधार आधारित ई केवाईसी, बोयोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी शामिल है।

- एम4एग्री से पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को कृषि और बागवानी से संबंधित सलाह जारी की जाती है।
- 97+ फीसदी देश के हिस्से में भूमि अभिलेख मानचित्रों का डिजिटलीकरण पूरा, 19 राज्यों में नागरिक अब घर बैठे डिजिटल हस्ताक्षरित और कानूनी रूप से मान्य भूमि अभिलेख डाउनलोड कर सकते हैं।
- 36+ करोड़ भूमि खंडों को विशिष्ठ भूमि पार्सल पहचान संख्या आवंटित की जा चुकी है। यह 14 अंकों की अल्फान्यूमेरिक कोड है जिससे बेनामी लेनदेन पर अंकुश लगता है।

9+ करोड़
किसान आईडी कार्ड बनाए गए।

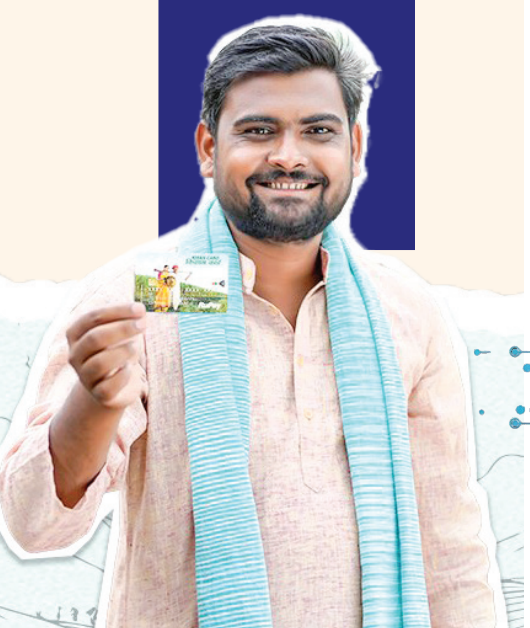

शिक्षा और कौशल

1.5 करोड़ उपयोगकर्ता iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, 4000+ डिजिटल पाठ्यक्रम हैं।

566+ करोड़
लर्निंग सेशन दीक्षा प्लेटफार्म पर हुए, 2 करोड़ से अधिक यूजर हैं।

- 800+ सरकारी वेबसाइट से जुड़ा है डिजिटल इंडिया भाषिणी, प्रतिदिन 1.5 करोड़ से अधिक एआई से जुड़े काम को पूरा करता है।
- 16 लाख से आधिक उम्मीदवार फ्यूचर स्किल्स प्राइम कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं जिनमें 85 फीसदी लाभार्थी टियर-2 और टियर-3 शहरों के हैं।
- 6.39 करोड़ ग्रामीणों को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) में प्रशिक्षित किया गया, लक्ष्य 6 करोड़ परिवारों में प्रति परिवार एक व्यक्ति के प्रशिक्षण का था।
- ई-काउंसलिंग, ई-ग्रंथालय, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी भी राह आसान कर रहा है।

इंटरप्रिन्योरशिप एंड मैन्युफैक्चरिंग

- 2.2+ लाख स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, यहां तकनीक लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं।
- स्टार्टअप इंडिया हब एक डिजिटल प्लेटफार्म है, जहां उभरते उद्यमी, निवेशक, मार्गदर्शक और इन्क्यूबेटर और सरकारी संस्थाएं एक मंच पर आती हैं, इनोवेशन और व्यापार को बढ़ावा मिलता है।

उभरती तकनीक

नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडियाएआई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे डिजिटल प्लेटफार्म उभरती तकनीकों को देश में बढ़ाने में सहायक बन रहे हैं।

खरीद, व्यापार एवं कर

- आइसगेट (**ICEGATE**) भारतीय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का पोर्टल है जिसे **ULIP**, मोटर व्हीकल इकोसिस्टम और **BSF** के साथ जोड़कर एक रियल-टाइम डेटा शेयरिंग नेटवर्क बनाया गया है, जिससे सीमा पर क्लीयरेंस और कार्गो प्रोसेसिंग तेज हो गई है।

18+ लाख करोड़ रुपये
की सरकारी खरीद GeM प्लेफार्म पर शुरु से अप्रैल, 2026 तक हुई।

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना

नए भारत के कार्यबल का सशक्तीकरण

श्रम बाजार को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार' योजना के माध्यम से देश में रोजगार सृजन का नया अध्याय गढ़ रही है। पहली बार देश में औपचारिक नौकरी से जोड़ने पर सीधी वित्तीय सहायता दी जा रही है। दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के लक्ष्य की ओर बढ़ते इस योजना में फरवरी 2026 तक करीब 56 लाख कर्मचारी हो चुके हैं पंजीकृत...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार को 'कल्याणकारी दान' नहीं बल्कि सशक्तीकरण के माध्यम के रूप में देखते हैं। यही विजन 'विकसित भारत 2047' के सपने को पूरा करने का मुख्य इंजन भी बनेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत फरवरी 2026 तक कुल 55.9 लाख पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों और 1.14 करोड़ पुनः कार्य शुरू करने वाले कर्मचारियों को नामांकित किया गया है। योजना के तहत, पहली बार नौकरी पाने वाले ऐसे कर्मचारी जिनका नया यूएएन (UAN) जनरेट हुआ है, वे अधिकतम 15,000 रुपये के प्रोत्साहन के पात्र हैं। यह राशि छह-छह महीने के अंतराल पर दो किस्तों में दी जानी है। वहीं दूसरी ओर, सरकार नियोक्ताओं (Employers) को भी प्रत्येक नए कर्मचारी पर छह महीने का स्थिर रोजगार प्रदान करने के बाद 3,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जानी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी, जिसके लिए 99,446 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार के लिए मिलना है। योजना में एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी ही पात्र होंगे। नई नौकरियों के सृजन से न सिर्फ युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि इससे आत्मनिर्भर भारत की नींव को भी मजबूती मिलेगी। भारत सरकार ने बजट 2024-25 में 'प्रधानमंत्री के रोजगार एवं कौशल विकास पैकेज' के अंतर्गत रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। योजना के दो भाग हैं- यह कर्मचारियों को सहायता प्रदान करती है और प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग देती है। ■

> *"आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यह संकल्प, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग-अलग सेक्टर में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

सूरत और दमन में करीब 23,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

आधुनिक कनेक्टिविटी और विकास का नया अध्याय

गुजरात के सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन में क्षेत्रीय विकास और मजबूत कनेक्टिविटी के नए युग के सूत्रपात के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को सूरत, दमन और लक्षद्वीप में करीब 23,000 करोड़ रुपये की सड़क, एयरपोर्ट, अस्पताल, ऊर्जा और औद्योगिक विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से न केवल ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राष्ट्र के आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को भी मिलेगी गति...

देश विकसित भारत के जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर दिन एक नया अध्याय जुड़ रहा है। कोई भी राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, विकास में किसी भी स्तर पर पीछे न रह जाए, इसलिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं। विकास की रफ्तार समाज में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए काम करते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को गुजरात के सूरत, केंद्र शासित प्रदेश दमन और लक्षद्वीप का दौरा किया। यहां आम लोगों की सुविधाओं के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं के उद्घाटन से जहां

> *ये दशक, दुनिया के लिए आपदा का दशक सिद्ध हो रहा है। पहले बड़ा कोरोना संकट आया, फिर जगह-जगह युद्ध... अब इतना बड़ा ऊर्जा संकट... इसने पूरी दुनिया को अस्त-व्यस्त कर दिया है। लेकिन मुझे बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

सूरत से देश को विकास परियोजनाओं की सौगातें

- उद्घाटन: 8-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रमुख पैकेज राष्ट्र को समर्पित।
- सूरत में 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल।
- पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार की परियोजना।
- रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र।
- सारिगाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम में उन्नत अपशिष्ट निपटान।
- शिलान्यास : जनजातीय क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के महत्वपूर्ण खंडों को चार लेन बनाना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा स्थित लार्सन एंड टुब्रो परिसर का दौरा किया, जहां उन्होंने कंपनी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किए जा रहे इनोवेशन को देखा।

एक ओर आम लोगों का जीवन सुखद होगा वहीं जिन परियोनाओं का शिलान्यास हुआ है उससे आने वाले समय में भविष्य की राह आसान होगी। सूरत में 18,800 करोड़, दमन में 2,970 करोड़ और लक्षद्वीप में 885 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।

सूरत में आयोजित कार्यक्रम में प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में गुजरात के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहां देश की 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के पांचवें हिस्से (50 गीगावाट) का उत्पादन होता है। राज्य हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया जैसे उभरते क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। पिछले 12 वर्षों में सौर ऊर्जा, इथेनॉल मिश्रण, रेलवे विद्युतीकरण, परमाणु ऊर्जा, ट्रांसमिशन नेटवर्क, गैस पाइपलाइन और बंदरगाह भंडारण क्षमताओं का बहुत व्यापक विस्तार हुआ है। पिछले कुछ समय से जारी वैश्विक संकट ने यह बताया है कि ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है।

हजीरा की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इस क्षेत्र को केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि, ऊर्जा, इस्पात, रक्षा उत्पादन और वैश्विक समुद्री व्यापार को समाहित करने वाला एक व्यापक, समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्णित किया। उन्होंने इस समुद्री-औद्योगिक केंद्र को 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का जीवंत प्रमाण बताया। देश के उन निराशावादी गुटों की कड़ी निंदा की जो आत्मनिर्भरता अभियान का उपहास करते हैं। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। समर्पित

लक्षद्वीप के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति

- आधारशिला : लगभग 885 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला।
- कलपेनी द्वीप और कदमत द्वीप दोनों के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बंदरगाह सुविधाओं का विकास होगा।
- बहुउद्देशीय घाटों के विकास से 300 मीटर तक की लंबाई वाले क्रूज जहाजों सहित बड़े यात्री जहाजों के लिए साल भर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- मछली प्रबंधन, ईंधन वितरण, बर्फ आपूर्ति और नाव मरम्मत के लिए एकीकृत सुविधाएं प्रदान होंगी।
- यह पहल समुद्री कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगी, स्थानीय मछुआरों की आजीविका में सहायता करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी और द्वीपों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देगी।

दमन को मिली विकास की सौगातें

- **उद्घाटनः** नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और नमो अस्पताल।
- **आधारशिलाः** आइकॉनिक ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर, एनआईएफटी परिसर।

प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून को प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया जो वैश्विक खेल विरासत में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है। पीएम मोदी ने कहा, "आज अहमदाबाद की धरती से विश्व की खेल विरासत में एक नया अध्याय जुड़ रहा है।" उन्होंने कहा कि अहमदाबाद यूनेस्को की विश्व धरोहर नगरी है और भारत के इस ऐतिहासिक शहर में इस आयोजन का होना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे-जैसे योगासन खेल का विस्तार होगा, वैसे-वैसे नई संभावनाएं भी विकसित होंगी। इससे खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और आयोजन प्रबंधकों के लिए नए करियर अवसर सृजित होंगे।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

माल गलियारा, बुलेट ट्रेन और वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी मेगा परियोजनाएं औद्योगिक और व्यापारिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच और तापी के आदिवासी क्षेत्रों में चार लेन के राजमार्ग बनाकर, सरकार यात्रा के समय और माल ढुलाई लागत को कम कर रही है। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कनेक्टिविटी लाकर, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें शिक्षा, चिकित्सा और बेहतर आय के अवसरों के लिए सुविधाएं प्राप्त हों।

दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पिछली यात्रा को याद किया। उन्होंने उल्लेख किया कि उस समय व्यक्त की गई उनकी भावना आज वास्तविकता में बदल चुकी है। यह क्षेत्र अब देश की विविधता और जीवंतता का गर्व से प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "दमन मिनी इंडिया का एक जीवंत उदाहरण बन गया है, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का निवास पूरे देश की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करता है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने दमन, दीव और दादरा एवं नगर हवेली में प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे सुशासन मॉडल की सराहना की। साथ ही उन्होंने वहां की कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने दमन के विकास की तुलना सिंगापुर की आर्थिक प्रगति से करते हुए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा कि 'नमो हवाई अड्डा' और 'दमनगंगा पुल' जैसे बड़े प्रोजेक्ट केवल स्थानीय बदलाव नहीं, बल्कि इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने वाले मील के पत्थर हैं। इस तरह के तमाम बुनियादी ढांचे के माध्यम से, भविष्य के संकल्पों के लिए एक मजबूत नींव तैयार किया जा रहा है।

केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव आ रहे हैं। पहले यहां के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मजबूरन पलायन करना पड़ता था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में धीरे-धीरे और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सरस्वती साइकिल योजना और सरस्वती विद्या योजना यहां की बेटियों के लिए मददगार साबित हो रही है। खेलो इंडिया जैसी पहल ने खेलों को महानगरों तक सीमित रखने की बजाय गांवों, कस्बों और छोटे क्षेत्रों तक पहुंचाया है। दीव भी एक एक प्रमुख 'बीच स्पोर्ट्स' गंतव्य के रूप में उभर रहा है और खेल पर्यटन को नई पहचान दे रहा है। ■

वीरता को सम्मान...

आज राष्ट्र न सिर्फ सीमा पर बल्कि अंदरूनी हिस्सों में भी आतंक और हथियारबंद कैडर से सुरक्षित है तो उसके पीछे हैं अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और असाधारण नेतृत्व देने वाले हमारे सैनिक, केंद्रीय सशस्त्र बल और पुलिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 8 जून, 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-2026 (चरण-I) में ऐसे ही 51 वीरों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रक्षा अलंकरण समारोह 2026 (चरण-1) में हुए शामिल और राष्ट्र के प्रति उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और नि:स्वार्थ सेवा पर व्यक्त किया गर्व...

रक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के वीरों को 7 कीर्ति चक्र (जिनमें 2 मरणोपरांत शामिल हैं), 15 वीर चक्र (जिनमें 3 मरणोपरांत शामिल हैं) और 29 शौर्य चक्र (जिनमें 1 मरणोपरांत शामिल है) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रदान किए। आइए जानें कुछ वीरता की कहानियां...

लांस नायक मीनात्वी सुंदरम् ए, कीर्ति चक्र

दि तोपखाना रेजिमेंट के मीनात्वी सुंदरम् ए ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कुलगाम में आतंकवादी को मार गिराया।

ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, फ्लाइंग पायलट, कीर्ति चक्र

भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए चार गगनयात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर ने राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने के दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। इस अदम्य साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रुप कैप्टर प्रशांत **Axiom**-4 मिशन में स्टैंडबाय मिशन पायलट भी रहे। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उत्कृष्ट शारीरिक सहनशीलता, मानसिक दृष्ठता एवं एकाग्रता का प्रदर्शन किया। **Axiom**-4 मिशन की तैयारी के दौरान उन्होंने अनजान खतरों का सामना करने की इच्छा शक्ति और अत्यधिक जोखिम भरी परिस्थितियों में संयम का भी प्रदर्शन किया।

लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, मरणोपरांत कीर्ति चक्र

दि सेना सेवा कोर सिक्किम स्काउट्स के लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी उत्तरी सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले इलाके में गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे। उसी दौरान गश्ती दल के सदस्य अग्नीवीर स्टेफेन सुब्बा अपना संतुलन खोकर एक नदी में फिसल गए। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। सुब्बा को किसी तरह से किनारे तक पहुंचाया। अग्निवीर की जान बच गई लेकिन तेज धारा के कारण कुछ पकड़ नहीं पाए। अधीनस्त को बचाते समय चट्टानों से लगी गंभीर चोट के कारण दम तोड़ दिया। असाधरण वीरता, निस्वार्थ और अडिग धैर्य के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया।

नायाब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, कीर्ति चक्र

किश्तवाड़ा जिले के दुर्गम और सुनसान जंगली क्षेत्र में सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए एक ही ऑपरेशन में दो आतंकवादियों को मार गिराया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा प्रदान किए गए वीरता पुरस्कारों का कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

शासी परिषद की बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता

दुनिया को प्रेरित करती रहती है भारत की विकास गाथा

नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है जो विकास के प्रत्येक पहलू में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश को तैयार करने के सरकार के दृष्टिकोण को कार्यान्वित करती है। आज भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है और 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून को नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में कहा कि दुनिया को भारत की विकास गाथा करती है प्रेरित...

नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। बैठक में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने भाग लिया। यह पहला अवसर था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, भारत की विकास गाथा दुनिया को प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकसित

रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार-विमर्श

शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्रियों और उप राज्यपालों ने एक साथ मिलकर समावेशी मानव विकास प्रारूप पर चर्चा की। साथ ही, बैठक में देश भर में उद्यमिता, कौशल विकास को बढ़ाने और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया। नीति आयोग की शासी परिषद में 26 से 28 दिसंबर, 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

नीति आयोग द्वारा 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

> *सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित हम सभी भारत की विकास यात्रा को गति देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयास 'विकसित भारत' के हमारे साझा दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।*
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

प्रमुख मुद्दों पर पीएम मोदी के दिशा-निर्देश

- राज्यों को युवाओं और एमएसएमई के लिए अवसर पैदा करने तथा उन देशों से सक्रिय रूप से निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- राज्यों को एक जिला एक उत्पाद को मजबूत करना चाहिए और रक्षा विनिर्माण में अवसरों का लाभ उठाना चाहिए।
- एआई को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और लोगों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से सुसज्जित किया जाना चाहिए।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए समन्वित प्रयास करना चाहिए।
- अल नीनो से उत्पन्न चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के साथ ही, राज्यों से जल संरक्षण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
- राज्यों ने वैश्विक भू-राजनीतिक संकट का सामना करने और भारत की क्षमता को मजबूत करने के लिए केंद्र के साथ एकजुटता व्यक्त की।

भारत की परिकल्पना हर राज्य, जिले, प्रखंड और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवा इसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, जिसमें लगभग 70 करोड़ भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि इस वर्ग को शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण की पहल पर ध्यान केंद्रित करें जो युवाओं को भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार करे।

इस वर्ष बैठक का विषय विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसका उद्देश्य आयु, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासकों ने प्रधानमंत्री मोदी को 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही और यह राज्यों की आकांक्षाओं, आशाओं, अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा चुनौतियों को दर्शाती है। ■

जिन्होंने मुश्किल समय में संभाली देश की कमान

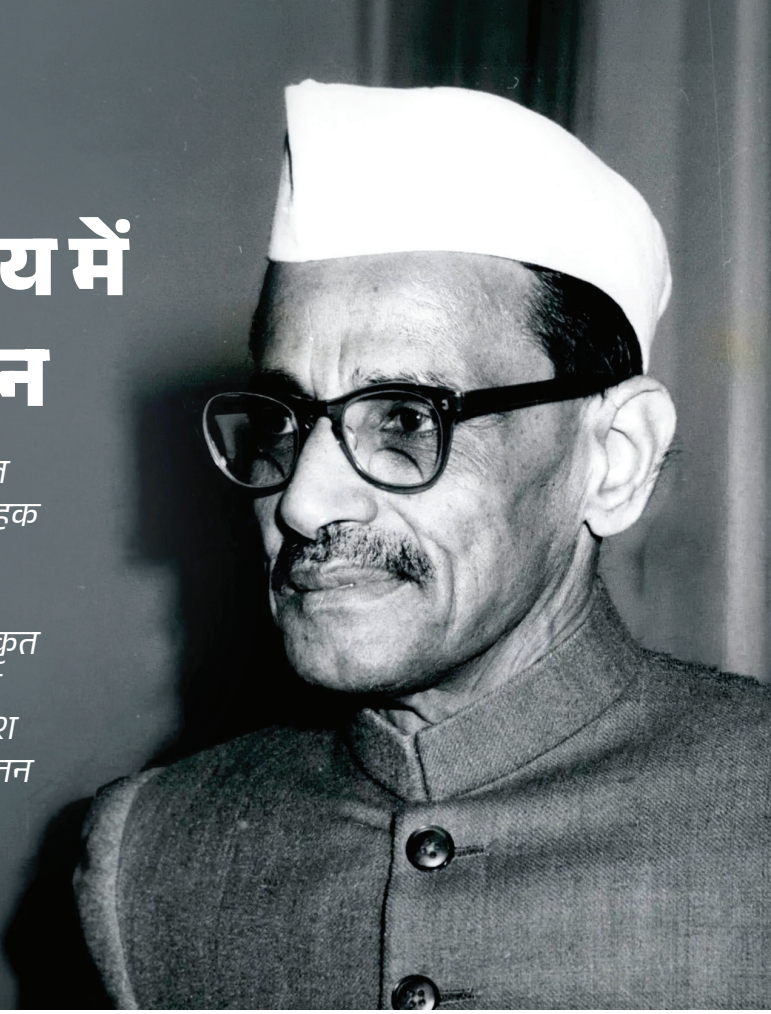

महान राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद व अर्थशास्त्री गुलजारी लाल नंदा ऐसे एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जो दो बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने देश की कमान संभाली जब देश के प्रधानमंत्री का आकास्मिक निधन हो गया था। सादगी और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने वाले नंदा को वर्ष 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। देश के विकास एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के प्रति उनका चिंतन आज भी राष्ट्र को करता है प्रेरित...

जन्म : 4 जुलाई 1898, मृत्यु : 15 जनवरी 1998

आदर्शवादी राजनीति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहे गुलजारी लाल नंदा ने दो बार देश की बागडोर संभाली फिर भी सरकारी सुख-सुविधाओं की चाहत नहीं रखी। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने जेल की यातनाएं सही, मजदूरों की आवाज बने और सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी सादगी का जीवन ही बिताया। उनका जीवन कोई प्रचार नहीं, बल्कि एक मौन तपस्या था। सत्ता में रहकर भी सत्ता से दूर, राजनीति में रहकर भी मूल्य और मर्यादा का साथ कभी नहीं छोड़ा। सादगी की मिसाल माने जाने वाले नंदा के बारे में कहा जाता है कि देश के कई बड़े पदों पर रहने के बावजूद उन्होंने किराये के मकान में अपनी जिंदगी गुजार दी।

4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट में जन्मे गुलजारी लाल नंदा ने लाहौर, आगरा एवं इलाहाबाद में अपनी शिक्षा प्राप्त की। देश की आजादी की लड़ाई की खातिर वर्ष 1932 में जेल जाना पड़ा। वह बाद में भी वर्ष 1942 से 1944 तक जेल में रहे। वर्ष 1937 में वे बंबई विधान सभा के लिए चुने गए एवं वर्ष 1937 से 1939 तक बंबई सरकार में संसदीय सचिव रहे। बाद में, बंबई सरकार के श्रम मंत्री (वर्ष 1946 से 1950 तक) के रूप में उन्होंने राज्य विधानसभा में सफलतापूर्वक श्रम विवाद विधेयक पेश किया। आजादी के बाद वह देश की राजनीति में सक्रिय हो गए और कई पदों पर रहे। वे वर्ष 1962 एवं 1963 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री एवं, 1963 से 1966 तक गृह मंत्री रहे।

पंडित जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु के बाद उन्होंने 27 मई, 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 13 दिन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर से 11 जनवरी 1966 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 13 दिन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। बाद के दिनों में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

गुलजारी लाल नंदा एक अच्छे राजनीतिज्ञ ही नहीं, अच्छे लेखक भी थे। एक लेखक के रूप में अपनी भूमिका का भी उन्होंने बेहतर ढंग से निर्वाह किया। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। 15 जनवरी 1998 को करीब 100 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी 'अस्थियां कुरुक्षेत्र में ही रहें।' उनकी इच्छानुसार उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को गुलजारी लाल नंदा स्मारक में रखा गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की देखरेख में, गुलजारी लाल नंदा मेमोरियल की आधारशिला 4 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद थे। ■

Narendra Modi
@narendramodi

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी हुकूमत के विरुद्ध अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया। उनका पूरा जीवन जनजातीय समाज के स्वाभिमान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा को समर्पित रहा। मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग करने की उनकी गाथा देश की हर पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का संचार करती रहेगी।

Rajnath Singh
@rajnathsingh

डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश, भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है। यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है। और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत कर रहा है।

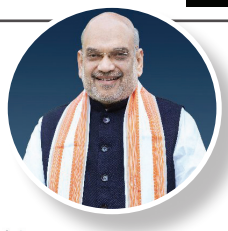

Amit Shah
@AmitShah

मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली-NCR को प्रदूषणमुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
पेट्रोल-डीजल चालित लगभग 2 लाख ट्रकों और 16 हजार बसों को चरणबद्ध तरीके से BS-4, इलेक्ट्रिक एवं CNG वाहनों में परिवर्तित करने की इस महत्वाकांक्षी पहल के लिए ₹9,585 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह निर्णय दिल्ली-NCR की वायु को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा तथा पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करके देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक पड़ाव पूर्ण करने पर आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का सभी सदस्यों द्वारा अभिनंदन किया गया।

प्रधानमंत्री जी की देशसेवा की यह ऐतिहासिक उपलब्धि 145 करोड़ देशवासियों के उन पर विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। राष्ट्र निर्माण के लिए उनके मार्गदर्शन में और कार्यकुशल नेतृत्व में कार्य करना निरंतर प्रेरणादायी है।

Giriraj Singh
@girirajsinghbjp

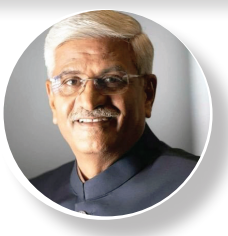

PLI योजना के माध्यम से भारत का वस्त्र क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।
राउंड-3 के तहत 22 नई कंपनियों को मंजूरी मिलने से ₹2,339 करोड़ के निवेश, ₹15,561 करोड़ के संभावित कारोबार तथा 36,217 नए रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा।
बढ़ता निवेश, सशक्त उद्योग और रोजगार सृजन के साथ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प निरंतर मजबूत हो रहा है।

Gajendra Singh Shekhawat
@gssjodhpur

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों का जीवन बदला है। बीज से बाजार तक किसान खुशहाली का बदलाव देख रहे हैं।

पीएम-किसान से सीधे मदद, e-NAM से बड़े बाजार, सॉयल हेल्थ कार्ड और नई तकनीकों से खेती ज्यादा आसान और फायदेमंद बनी है। फसल बीमा और मत्स्य संपदा जैसी योजनाओं ने भी अन्नदाता को नई ताकत दी है।

पीएम मोदी ने की नई पीढ़ी के योगदान की प्रशंसा

युवा भारतीय देश और दुनिया के भविष्य को दे रहे आकार

पीएम ने कहा कि भारत के युवा विज्ञान और तकनीक से लेकर विनिर्माण, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं

भारत दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप डेस्टिनेशन में से एक

उद्यमशीलता को दिया बढ़ावा

छोटे कस्बों और गांवों से आगे आए युवा

खेलों में भी बढ़ा रहे देश का गौरव

प्रधानमंत्री ने फ्रांस में 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम को संबोधित किया

वैश्विक समाधानों का उपभोक्ता ही नहीं, प्रदाता भी बना भारत : मोदी

भारत ने 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों के लिए बनाया सुलभ : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सस्ता और आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए व्यापक काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए ऐसे सभी प्रयासों को आगे भी जारी रखेगी।

पीएम बोले- स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए जारी रहेंगे प्रयास

सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को इस बात पर गर्व है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के लिए जाना जाता है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा, पीएम भारतीय जनऔषधि परियोजना जैसी योजनाओं ने दवाओं, स्टेंट व घुटने के प्रत्यारोपण को सस्ता बनाया है। इससे लाखों लोगों को राहत मिली है और इलाज का खर्च कम हुआ है। देश में मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से चिकित्सा शिक्षा पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुई है। एजेंसी

मुलाकात

भारत नवाचार का देश है : मैक्रों

मोदी और मैक्रों ने कलाकृतियों का अवलोकन किया

भारत-फ्रांस ने रक्षा, तकनीक पर बढ़ाए कदम, कई मुद्दों पर चर्चा

फ्रांस में मोदी-मैक्रों ने द्विपक्षीय बैठक की

मैक्रों की सेल्फी, भारतीयों में उत्साह

नए लक्ष्य तय किए

स्पेस सेक्टर में बढ़ेगी भागीदारी

पीएम मोदी भारतीय समुदाय से मिले। होटल में एक बच्चे को दुलार भी किया।

एआई से स्पेस तक, भविष्य की तस्वीर साफ

'महिलाओं को पूरी क्षमता दिखाने को राजग सरकार ने दिया माहौल'

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राजग सरकार के प्रयास सम्मान, अवसर और सशक्तीकरण में निहित हैं और इनसे ऐसा माहौल तैयार हुआ है जहां महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकती हैं और राष्ट्र निर्माण में और अधिक मजबूती से योगदान कर सकती हैं।

मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 12 वर्षों में राजग सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, और यह विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी • फाइल फोटो

'नारी शक्ति' को आगे बढ़ा रहा सरकार का माडल : शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का "महिला नेतृत्व विकास" माडल 'नारी शक्ति' के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण को आगे बढ़ा रहा है। शाह ने एक पोस्ट में कहा, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" से लेकर उज्ज्वला योजना के

विकसित भारत के लिए राज्यों के बीच संवाद सहयोग, अनुभवों का आदान-प्रदान जरूरी : मोदी

नीति आयोग की बैठक में पीएम ने कहा-वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत तेजी से बढ़ रहा आगे

70 करोड़ युवा भारत की सबसे बड़ी पूंजी

विश्वभर के नेताओं ने पीएम को दी बधाई

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने मोदी के परिवर्तनकारी शासन की जमकर सराहना की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने एक पत्र के माध्यम से इस उपलब्धि को भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता और जनता के मोदी सरकार में निरंतर विश्वास का प्रतीक बताया।

जागरण ब्यूरो के अनुसार, दिसानायके ने लिखा -" भारत गणराज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर सरकार और श्रीलंका की

• श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके ने लिखा पत्र, कहा-यह मोदी सरकार में निरंतर जनता के विश्वास का प्रतीक

• पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी को रोल माडल व लीडरशिप का उदाहरण बताया

नरेन्द्र मोदी•

उल्लेखनीय है। इससे न केवल शासन की उत्कृष्ट क्षमता, बल्कि आम लोगों के जीवन में ठोस सुधार लाने और चुनौतियों के बीच भी

एक व्यक्तिगत वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को "एक रोल माडल व लीडरशिप का उदाहरण" बताया। कहा- "20 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से निकालकर सामान्य जनजीवन में लाना अद्भुत उपलब्धि है।" उन्होंने भारत से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई।

एएनआइ के अनुसार, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने भी मोदी को यह कहते हुए बधाई दी कि उनके नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में एक प्रमुख आवाज के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि एक साधारण शुरुआत से लेकर 1.40 अरब लोगों

रामसर स्थलों का शतक...

भारत का 100वां रामसर

जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य

भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश के बलिया का जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी नेटवर्क में जुड़ गया है। यह अभयारण्य पक्षी विविधता से समृद्ध है और सुरहा ताल के नाम से पहचान रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों की शताब्दी पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को और मजबूत करती है। यह ऐसा शतक है जो केवल संख्या नहीं, बल्कि संरक्षण, जैव विविधता और सतत विकास के प्रति भारत के संकल्प की कहता है कहानी...

रामसर स्थल की कहानी...

- भारत, ईरान के रामसर में 1971 में हस्ताक्षरित 'रामसर कन्वेंशन' के अनुबंधित पक्षों में से एक है। भारत 1 फरवरी 1982 को इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता बना।
- रामसर स्थल वे आर्द्रभूमि हैं जिन्हें 'रामसर कन्वेंशन' के तहत मान्यता प्राप्त है।
- भारत में जहां 31 वर्षों में यानी 2014 तक 26 रामसर स्थल घोषित हुए, वहीं पिछले 12 वर्षों में 74 नए स्थल इसमें जुड़े हैं।
- इंदौर और उदयपुर भारत के पहले रामसर आर्द्रभूमि शहर बने (जनवरी 2025)।

12 साल में 4 गुना हुए रामसर साइट

> *प्राकृतिक परिवेश और आर्द्रभूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इस उपलब्धि से परिलक्षित होती है। ये प्रयास जैव विविधता को संरक्षित करने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य का निर्माण करने में सहायक हैं।*
>
> **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 1-15 जुलाई, 2026

आरएनआई DELHIN/2020/78812 (प्रकाशन तिथि- 16 जून 2026, कुल पृष्ठ-42)

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक
कंचन प्रसाद
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित